Seventeenth Loksabha

an>

Title: Central Universities (Amendment) Bill, 2022(Consideration and Bill Passed)

माननीय सभापति: आइटम नंबर 18, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022.

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।" …(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके सामने और आपके माध्यम से सदन के सामने केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का एक संशोधन प्रस्ताव लेकर आया हूं। …(व्यवधान) देश में जिस प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ है, जिस प्रकार का मल्टी मोरल, मल्टी सैक्टोरल इन्फ्रास्ट्रक्चर का रूप बनने लगा है, उसके लिए उपयुक्त मानव संबल की भी आवश्यकता है, अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स की भी आवश्यकता है।…(व्यवधान) उसको ध्यान में रखते हुए सरकार का यह निर्णय हुआ है कि हमें एक वैश्विक स्तर की ग्लोबल स्टैंडर्ड मल्टी मोरल, मल्टी सैक्टोरल एक एकैडमिक इको सिस्टम, नॉलेज इको सिस्टम बनाने की आवश्यकता है।…(व्यवधान) उसी के तहत एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हमारी सरकार के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की जो एक दूरदृष्टि है कि एक 'गति शक्ति मिशन' बना है। गति शक्ति परिकल्पना के अंतर्गत सारे विभागों का एक प्रकार से एकीकरण करके, नीति के लिए, नियम के लिए इसका एक नया ढांचा बनता दिख रहा है।…(व्यवधान) इसमें ट्रांसपोर्टेशन के सारे विभाग, रेलवे,

रोड सैक्टर, वाटर वेज़, एविएशन सैक्टर, कोर सैक्टर तथा आईटी जैसे आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन सबको सभी प्रकार के संवाद की, दूरसंचार की, गमनागमन की व्यवस्था को गति शक्ति के प्लेटफॉर्म पर एक करने की आज योजना बन रही है, क्रियान्वित हो रही है।...(व्यवधान) इस प्रकार का ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में देश आज जुटा है।...(व्यवधान) उचित होगा कि इस प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मानव संबल भी वैसा ही बने।...(व्यवधान) इसीलिए मैने कहा, मल्टी सैक्टोरल, मल्टी मोरल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी, वैसे स्तर का एक विश्वविद्यालय बने।...(व्यवधान) रेलवे विभाग की अगुवाई में वर्ष 2018 से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी चल रही है।...(व्यवधान) आज उसकी आवश्यकता हुई है, उसकी परिधि को सर्वव्यापी करना, सर्वदेशी करना, इसीलिए यह संशोधन प्रस्ताव विश्वविद्यालय, 2009 कानून में हम लेकर आए हैं। इसे आपके विचारार्थ, सदन के विचारार्थ हम स्थापित कर रहे हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): आदरणीय सभापति जी, मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 के समर्थन में खड़ी हुई हूं। मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूं क्योंकि आपने मुझे केन्द्र सरकार द्वारा पारित किए जाने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2022 के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही शिक्षा का अत्यधिक महत्व रहा है। शिक्षा न केवल मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी अति आवश्यक है। शिक्षा न केवल मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी अति आवश्यक है । शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार प्रदान करना और तकनीकी रूप से देश को उच्चता के शिखर पर पहुंचाना है। रेल का परिचालन अपने आप में ही एक जटिल प्रणाली के जरिए होता है | विभिन्न सिस्टम आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इसमें अलग-अलग तरह

की विशेषताएं एवं तकनीकी स्किल्स की जरूरत होती है | इन सिस्टम और स्किल्स को विकसित करने में वर्षों लग जाते हैं।

आदरणीय सभापति जी, पिछले कुछ वर्षों में रेलवे में नई नई तकनीकें आई हैं, जैसे नई सिग्नलिंग प्रणाली (कवच), नई ट्रेन (वंदे भारत) जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से यात्रा के समय को कम करना, उसे अधिक सुखमय बनाना और शत-प्रतिशत सुरक्षा की गारंटी देना रहा है । इतनी जटिल तकनीकी प्रणाली को चलाने के लिए कर्मियों को एक गहन आरंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है, और समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी कराए जाते हैं, क्योंकि रेल सेवा में आने से पहले उनके पास वह विशेषज्ञता और तकनीकी स्किल्स नहीं होते जो उस काम के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे में हमें तकनीकी रूप से शिक्षित प्रशिक्षित युवक - युवतियों की आवश्यकता है, जिनकी मूल तकनीकी शिक्षा में ही ऐसे तत्वों का समावेश हो कि वे पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ ही ट्रेन संचालन की बारीकियों को पूरी तरह से जान जाएं ताकि उन्हें तुरंत काम पर लगाया जाए।

आदरणीय सभापति जी, दुनिया में हर बड़े रेलवे ने रेलवे प्रणालियों के अध्ययन, शोध और स्किलिंग के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गये हैं, जैसे – मैसाचुसेट्स सेंटर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका(1861), रेलटेक यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, अमेरिका (1867), रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, जापान (1986), मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, रूस (1896), बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन, इंग्लैंड (1972) और बीजिंग जियाओटोंग यूनिवर्सिटी, चीन (1896)।

आदरणीय सभापति जी, अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा । बिग डाटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी। जो उच्च स्तरीय तकनीकी योग्यता रखते हैं। वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह और भी जरूरी हो गया है।

इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018 में एक नई शुरुआत केंद्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (NRTI) के रूप में की गई। इस संस्थान में पाठ्यक्रमों को इस तरह से गठन किया गया है कि यहां से पास होने वाले छात्र रोजगार एवं स्वरोजगार के काबिल हों।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी का भी यही कहना है कि हम भारत में एक ऐसा इको सिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां भारत के नौजवान रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजन करने वाले बनें। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा के नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट (NRTI) को केंद्रीय विश्व विदयालय (गति शक्ति) का दर्जा देने के निर्णय को मंजूरी प्रदान करनी है। जिससे इसे गतिशक्ति विश्व विदयालय का दर्जा मिलेगा, जिससे इसकी क्षमता और बढ़ेगी, यहाँ और भी नए पाठ्यक्रम चलेंगे।

इसका लाभ न केवल गुजरात के युवक-युवतियों को मिलेगा, बल्कि देश भर के युवाओं को मिलेगा। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल रेल परिवहन से जुड़े हुए विषयों के शिक्षण के लिए स्थापित नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें मेट्रो रेल, सड़क मार्ग, जलमार्ग, वायुमार्ग आदि से जुड़े हुए पाठ्यक्रम का भी समावेश किया गया है। ... (व्यवधान) आदरणीय सभापति जी, इस विश्वविद्यालय में ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक एजुकेशन और कौशल विकास से सम्बंधित पाठ्यक्रमों के साथ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी के साथ-साथ एप्लाइड रिसर्च को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। इस विश्वविद्यालय का केंद्रीय कैम्पस मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा को मिला है। ... (व्यवधान) मैं आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का अपनी और वडोदरा की जनता की ओर से बहुत ही आभार प्रकट करती हूं। साथ ही मैं आदरणीय धर्मेन्द्र प्रधान जी, आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी जी और रेल राज्य मंत्री दर्शना बहन का अभिनंदन करती हूं और आभार प्रकट करती हूं। देश में अलग-अलग स्थानों पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैम्पस स्थापित होने वाले हैं, लेकिन उनका मुख्य कैम्पस वडोदरा में होगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूं। ... (व्यवधान) आदरणीय सभापति जी, मेरे संसदीय

मत क्षेत्र वडोदरा में गतिशक्ति विश्वविद्यालय को मंजूरी देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का और माननीय रेल राज्यमंत्री दर्शनाबेन जरदोश जी का सहृदय धन्यवाद करती हूँ। उक्त सभी कार्यों के समय से संपन्न होने के कारण निश्चित रूप से देश के विकास को नया आयाम मिलेगा। ये सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से संभव हो पा रहे हैं। … (व्यवधान)

अंत में, मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : प्रोफ़ेसर सौगत राय जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: श्री कौशलेन्द्र कुमार जी।

… (व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, सरकार द्वारा यह बिल मुख्य रूप से गुजरात राज्य के वडोदरा स्थित रेलवे महाविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नाम गतिशक्ति विश्वविद्यालय करने के लिए लाया गया है। यह स्वागत योग्य है। अब सरकार का विचार 100 लाख करोड़ रुपये रेलवे के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं में खर्च करने का है। यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगा, इसकी आने वाले समय में देश को जरूरत भी है। गतिशक्ति केन्द्रीय विश्वविद्यालय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, नागर विमानन, पोर्ट्स, शिपिंग और जल परिवहन मंत्रालयों के लिए भी सहायक सिद्ध होगा।

मैं बिहार प्रदेश से आता हूँ। विश्व धरोहर के रूप में यहां की धरती पर प्राचीन पठन-पाठन के लिए नालंदा को जाना जाता है। नालंदा अन्तर्राष्ट्रीय

महाविद्यालय के लिए काफी सहायता प्रदान की गई है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इसी क्रम में नालंदा में नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के प्राचीन शास्त्रों एवं विषयों की पढ़ाई और शोध भी किया जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए। इससे वहां पढ़ाए जा रहे विषयों के साथ साइंस की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के साथ पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी ।

सभापति जी, बिहार राज्य की पटना यूनिवर्सिटी एक प्राचीन यूनिवर्सिटी है। इसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार काफी प्रयासरत हैं। केन्द्र सरकार द्वारा भी आश्वासन मिला है। किन्तु, इस दिशा में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की भी यह इच्छा थी। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने अपनी पिछली बिहार यात्रा के दौरान भी आश्वासन दिया था।। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार की जनता से वादा किया था कि पटना यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। ... (व्यवधान)

मैं सरकार से माँग करता हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी और नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने जवाब में पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव जरूर रखेंगे। ... (व्यवधान)

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन के लिए मेरा व बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका और आपके साथ-साथ अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं। ... (व्यवधान) केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत एक मानित विश्वविद्यलाय को एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के

रूप में परिवर्तित करने का उपबंध करता है, जिसको गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। यह एक सराहनीय कदम है। रेलवे की तरह ही मेट्रो, एविएशन, शिपिंग, हाइवे, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक्स भी टेक्निकली कॉम्पलेक्स है। इन क्षेत्रों में भी बहुत अधिक तकनीकी विकास हुआ है, जिसके कारण वहां अच्छे और उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा और योग्यता की भारी आवश्यकता है। लेकिन, गति शक्ति विश्वविद्यालय को परिवहन क्षेत्र में अत्याधुनिक और तकनीकी के निर्माण की सुविधा प्रदान करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसके लिए क्षमता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ-साथ प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्यथा, पूरी नीति के विफल होने का खतरा पैदा हो सकता है। ... (व्यवधान)

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे लाखों बच्चे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करके भटक रहे हैं। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐसे विश्वविद्यालयों में स्पेशल डिप्लोमा या स्पेशल कोर्स कराकर उनको नौकरी देने का काम किया जाए। ... (व्यवधान) इस देश में यह पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय है और देश में कुशल श्रमिकों की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे कई और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। उसे देखते हुए सरकार शिक्षा, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि कई क्षेत्रों में गति शक्ति ब्रांड को लागू करने के बारे में विचार कर सकती है।

परिवहन क्षेत्र में व्यापार विस्तार, अनुसंधान और विकास के लिए आउट ऑफ द बॉक्स दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मंत्रालय को दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन मॉडलों को अध्ययन करने के बारे में भी विचार करना चाहिए, जिन्हें भारत में दोहराया जा सकता है। गति शक्ति ब्रांड का उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सतत् विकास जैसे कई क्षेत्रों में लाभ उठाया जा सकता है। इससे देश में प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और उससे भारत को ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। ... (व्यवधान)

इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के प्रोफेसरों की कमी के ऊपर भी आकृष्ट

कराना चाहूंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी भी संविधान के अनुरूप आरक्षित कोटे को पूरा नहीं किया गया है। ... (व्यवधान) कई अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करके रिक्त पदों की जगह होने के बावजूद भी भरा नहीं गया है, जबकि उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि एक पद हेतु आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती, लेकिन विश्वविद्यालय यदि एक है तो समस्त नौकरियों को जोड़कर उसकी संख्या के अनुसार आरक्षण दिए जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी मांग करती है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को अनिवार्य रूप से दिए जाने की मैं मांग करती हूं।

इसके अलावा, अभी हाल में लगभग दस दिन पहले हिन्दू अखबार में छपे एक आर्टिकल के अनुसार आईआईटी, दिल्ली के 8 विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों द्वारा पीएचडी हेतु कुल 637 पदों के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

लेकिन उनमें से एक भी पद की भर्ती नहीं की गई थी, यह बहुत ही दुखद है। इस तरह के आंकड़े देखने के बाद सहज ही समझा जा सकता है कि एससी, एसटी और ओबीसी के साथ शिक्षा में भेदभाव का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है।...(व्यवधान) इसके साथ ही साथ इस सदन में संविधान की दुहाई देने वाले ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं तमाम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आए दिन देखने को मिलती हैं, लेकिन सरकार कभी भी गंभीर होकर दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करती है। इस तरह से उनका मनोबल बढ़ता है।...(व्यवधान)

महोदय, मेरी सरकार और माननीय मंत्री जी से मांग है कि ऐसे प्रकरणों पर सरकार गंभीर रूप से ध्यान दे और ऐसी चीजें आगे न बढ़ें। इसी के साथ-साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूं।...(व्यवधान)

रेल मंत्री; **संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव) :** सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र

मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि वे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत के पूरे शिक्षा स्ट्रक्चर को बदलने के लिए एक नया आयाम दिया है, एक नया प्रयास आरंभ किया है।...(व्यवधान) मेरे वरिष्ठ साथी माननीय श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, उसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण आज का यह बिल है, जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक में अमेंडमेंट के लिए है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, आप सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत ही कॉम्पलेक्स सेक्टर है। स्पेशली अगर हम रेलवे और मेट्रो में देखें, तो ये तो अपने आप में ऐसे सेक्टर्स हैं, जिन सेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता।...(व्यवधान) मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। रेलवे में कॉम्प्लेक्सिटी में तो यह परिस्थिति होती है कि मान लीजिए कि अगर पांव में चोट लगे, तो दर्द पांव में होता है, लेकिन रेलवे जैसी कॉम्प्लेक्सिटी में यह होता है कि अगर पांव में चोट लगती है, तो दर्द हाथ में होगा।...(व्यवधान) अगर इतनी कॉम्पलेक्स प्रणाली को ठीक से चलाना है, आगे बढ़ाना है, एक अच्छे तरीके से देश की जो एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को आगे ले जाना है, तो टेक्निकल एजुकेशन में एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की बहुत बड़ी जरूरत है।...(व्यवधान) इसी धारणा और विचार के साथ वर्ष 2018 में नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट की व्यवस्था की गई थी, जो कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी थी।... (व्यवधान) उसके अच्छे रिजल्ट्स देखकर, आज एक बड़े पैमाने पर गति शक्ति यूनिवर्सिटी की परिकल्पना सदन के सामने प्रस्तुत है।...(व्यवधान)

सभापति जी, इस गति शक्ति विश्वविद्यालय में मेट्रो, रीज़नल रेल, लॉजिस्टिक्स, हाइवे, ब्रिज, पोर्ट, इन सारे सेक्टर्स से रिलेटेड जितनी टेक्निकल नॉलेज की, जितनी इंजीनियरिंग की, जितनी उसकी इकोनॉमिक्स और जितना उसके फाइनेंस का विषय है, इसमें वे सारे विषय लिए जाएंगे।...(व्यवधान) अगर आप देखेंगे, तो विश्व के करीब-करीब सभी देशों जैसे अमेरिका में इलिनाइज यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है।...(व्यवधान) जापान में आरटीआरआई है, चाइना में बीजिंग में है, रशिया में है, करीब-करीब हर बड़े देश में, जहां कहीं भी रेलवे का बड़ा नेटवर्क है, उन सभी जगह एक यूनिवर्सिटी की परिकल्पना हुई

है। उसी कल्पना के साथ, उसी प्रकल्प और उसी भावना के साथ गति शक्ति यूनिवर्सिटी का डेवलेपमेंट होगा।...(व्यवधान)

सभापति जी, इस यूनिवर्सिटी के पांच बड़े ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ट्रांसपोर्ट फोकस्ड कोर्स का होगा। ऐसे कोर्सेज़ जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होंगे, हाइवे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड, इसमें हर तरीके के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोर्सेज़ होंगे।...(व्यवधान) दूसरा स्किल डेवलेपमेंट का होगा, जो कि स्किल इंडिया का फ्रेमवर्क है। उसी फ्रेमवर्क में स्किल डेवलेपमेंट का होगा।...(व्यवधान)

तीसरा इसमें अप्लाईड रिसर्च होगा। ऑपरेशन रिसर्च, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ब्रिज, टनल, मैरीटाइम, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, इन सबका स्किल डेवलेपमेंट का अप्लाईड रिसर्च का फ्रेमवर्क रहेगा।...(व्यवधान) चौथा टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट होगा। टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलेप हो, उसकी बहुत जरूरत है। उसका एक फ्रेमवर्क रहेगा।...(व्यवधान) पांचवां ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का होगा। इन पांचों ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जाया जाएगा।...(व्यवधान)

अभी इस यूनिवर्सिटी का हैडक्वार्टर बड़ौदा में है।... (व्यवधान) जैसा अभी माननीय सांसद संगीता जी ने कहा है तथा और भी वक्ताओं ने कहा है कि देश में कई जगहों पर इसके ऑफ कैम्पस बनेंगे।... (व्यवधान) उन ऑफ कैम्पस में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की तरह व्यवस्था होगी। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, जिनको बहुत अच्छे से पढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके।... (व्यवधान) इन सबको ध्यान में रखकर काम किया जाएगा।... (व्यवधान)

सभापति जी, हमारे देश में बातें होती हैं। हम कई बार हिन्दी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तेलुगू मीडियम और तमिल मीडियम की बातें करते हैं।... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने डिजिटल इंडिया के तहत एक नया डिजिटल मीडियम प्रारम्भ किया है, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज करके एजुकेशन में, हेल्थ में कई तरह के प्रभावशाली प्रयास हुए हैं।...

(व्यवधान) इस यूनिवर्सिटी में डिजिटल मीडियम का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा।... (व्यवधान)

सभापति जी, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क में 'गति शक्ति विश्वविद्यालय' का सदन के सामने प्रस्तुतिकरण है।... (व्यवधान) मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह छात्रों के भविष्य का विषय है। मैं अपोजिशन से विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि वे छात्रों के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ न करें।... (व्यवधान) वे अपनी-अपनी सीट्स पर बैठें, अपनी-अपनी जगह पर बैठें और इस बिल का सब एकमत होकर अनुमोदन करें।... (व्यवधान)

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on the Central Universities (Amendment) Bill, 2022. … (*Interruptions*)

I, on behalf of the Biju Janata Dal Party and also on behalf of our leader, Shri Naveen Patnaik *Ji*, support the Bill. If you go through the background, summary, and amendments to the Bill, you will find that it is a very good Bill. Definitely, it will help to have *swarojgar*. जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि यंग इंडियन्स को स्वरोज़गार और अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। … (*Interruptions*) The Government is going to name this University as Gati Shakti Vishwavidyalaya. This will be named after the Government's flagship programme of PM Gati Shakti National Master Plan for Multi-modal Connectivity to expand its jurisdiction all over the country. I support this amendment in the Central Universities (Amendment) Bill, 2022.

Hon. Chairperson, Sir, there is no doubt that this Vishwavidyalaya will bring a drastic change in the transport sector of the country. … (*Interruptions*) In my view, while bringing these amendments, we should also see and examine the criteria for setting up Central

Universities in the country because as of now, of all the States and Union Territories, New Delhi tops the chart of the Central Universities with as many as seven, that is, the highest number of Central Universities. … (*Interruptions*) It is followed closely by Uttar Pradesh with six Central Universities and Bihar with four Central Universities. The States of Manipur, Andhra Pradesh, and Telangana contribute with their three universities to the national number of Central Universities. The total number of Central Universities in India is 54.

In my State of Odisha, we have only one Central University. That is in the Adivasi area of Koraput district. In the said area, about seventy to eighty per cent or may be ninety per cent people are Adivasis. When I once visited that place, I found that still there is no academic facility. The vacancies for the posts of Professors and Assistant Professors have not been filled up. Even the research activities are not being done. Moreover, I am not sure about the present Vice Chancellor. I do not know the present situation there. … (*Interruptions*) But the Vice-Chancellor is staying at Bhubaneswar and not at Koraput. This is very unfortunate. So, I want to bring to the notice of the hon. Minister to look after it.

Sir, one of the objectives for setting up Gati Shakti Vishwavidyalaya is to increase the participation of young India talent who constitute about 25 per cent of our population and they will get specialized training in the transportation sector and carry out critically needed research and development.

Sir, university means only research activities. So, this will definitely help to have research facilities and to have new innovations. It will create innovative technologies which will encourage local

manufacturing by making the nation self-reliant. Keeping in view all the above things, first of all, we have to examine the criteria for setting up of Central Universities in the country. There has been no uniformity in setting up of a Central University. We have seen that some small States have more Central Universities than the big States. This has been encouraging migration from one State to other State and to check such migration, there is a need to have policy for setting up of a Central University in States.

Sir, we have a large number of youth in my State of Odisha but we have only one Central University. There may be a curriculum to be taught in the programme offered by the University which is aligned with the international best practices and based on the requirements and developments of the transportation sector of the country which are incorporated under Gati Shakti Vishwavidyalaya. However, a very small number of students from our State will get benefitted from this University.

Through you, Sir, I, therefore, demand the Union Minister to set up more Central Universities so that the objectives of Gati Shakti Vishwavidyalya are achieved and the youth of Odisha can equally contribute for the national development and economic growth of the country.

The hon. Minister has also mentioned that there is a proposal to have more such universities in the country. Sir, GSV will integrate the existing central training institutes of Indian Railways as the campus is utilizing the existing capacity.

Expertise, resources and the infrastructure will not only be leveraged to offer degree programmes but also it will give industry-

based courses.

Sir, I have a doubt that these existing Indian Railway institutes will be sufficient to meet the objectives and targets of 5,000 students in the coming five years in the GSV. So, Sir, there is also a need to encourage participation of State Universities and also private universities and to affiliate them with the Gati Shakti Vishwavidyalya. This will also help the Government to achieve the objectives of the Bill.

Sir, in conclusion, it is a laudable initiative towards enabling development of the transport sector. The scope for discussion should have a pro-development approach in additional ways so that the Government can attract, retain, develop talent, promote research and provide infrastructure.

With these words, I support the Bill. Thank you, Sir.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I came with a mind to support the Central Universities (Amendment) Bill, 2021. But after coming here, ...

*

माननीय सभापति : सौगत दा, आप बिल पर बोलिए। प्लीज, बिल पर बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : बिल पर कही गई बातों के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सर, ये किस पर बोल रहे हैं? ... (व्यवधान) ये बिल पर नहीं बोल रहे है। आप इनको रोकिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : बिल के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री सौगत राय जी ने बिल के अतिरिक्त जो बोला है, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

PROF. SOUGATA RAY: That is why, we will walk out. … (*Interruptions*)

14.35 hrs

At this stage, Prof. Sougata Ray and some other

hon. Members left the House.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा में अपनी पार्टी की तरफ से भाग ले रहा हूं। शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और कौशल को प्रदान करती है।… (व्यवधान) यह सीखने की निरंतर, धीमी और सुरक्षित प्रक्रिया है, जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और हमारे जीवन के साथ ही खत्म होती है।… (व्यवधान) सभी के लिए जीवन में बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है। वर्तमान युग में शिक्षा का महत्व बहुत आगे बढ़ गया है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर हम अपना भविष्य बेहतर और उज्ज्वल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।… (व्यवधान)

महोदय, हमारे देश में लगभग हर राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय मौजूद हैं। उत्तम और उच्चतर शिक्षा हेतु इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकता पड़ी। पहले हमारे देश में ऊंचे स्तर की शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थीं। … (व्यवधान) इस कारण इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी पड़ी। हमारे देश में कुल 49 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 45 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एक कृषि मंत्रालय, एक विदेश

मंत्रालय और एक जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।... (व्यवधान) साल 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून पारित किया गया था। इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालयों के गठन और उससे संबंधित फैसले लेने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार अब इसी कानून में संशोधन करके गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाने का रास्ता साफ कर रही है।... (व्यवधान)

मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 का समर्थन करता हूं। यह विधेयक गुजरात के वडोदरा स्थित एनआरटीआई, जो अभी तक एक डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी है, जो कि इस विधेयक से एक गति शक्ति विश्वविद्यालय बनने के बाद स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा। इस संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय के पास होगा।... (व्यवधान)

महोदय, इस विधेयक के तहत इस यूनिवर्सिटी के दायरे को भी बढ़ाया जाएगा, जबकि पहले यह रेलवे मामलों तक ही सीमित था, लेकिन अब इसमें पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर और इस क्षेत्र में हो रहे सभी आधुनिक विकास कार्यों की शिक्षा इस यूनिवर्सिटी में दी जाएगी।... (व्यवधान) छात्रों को इस दिशा में रिसर्च के अवसर भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों के तहत यह एक बहुत अच्छा विधेयक है। मैं इस सरकार द्वारा लाये गए इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।... (व्यवधान)

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Central University (Amendment) Bill, 2022 which has been brought forward by the Government to convert the National Railways and Transportation university into a full-fledged university called the *Gati Shakti Viswavidyalaya.*

Sir, I would like to present my inputs on how the proposed university can act as a catalyst to boost growth of the transport sector.

The Union Government has identified the transport sector as one of the key drivers of economic growth. Transport sector is vital for

economic growth as it contributes around 6 per cent of the GDP and employs over 22 million people. The Union Government has been making significant progress in the transport sector through initiatives like the PM Gati Shakti, Dedicated Freight Corridors and the Bharatmala Pariyojana. Freight loading in the Indian Railways has been the highest at 1418.10 metric tonnes during 2021-22. Dedicated Freight Corridors in the Eastern and Western regions of the country are also being developed.

Establishing the Gati Shakti Vishwavidyalaya would address the skill gap in the transport sector. India's work force in the transport and logistics sector has reached 2.5 crores and an estimated additional work force of three crores would be needed in the coming decade. The cost of logistics in India is one of the highest in the world which is nearly 14 per cent of the GDP. The Gati Shakti Vishwavidyalaya would help in reducing the cost of logistics by skilling the work force. There is a need to manage the Central Universities in an efficient manner and vacant faculty positions are a cause of concern. According to the Ministry of Education, over 6500 faculty positions are vacant in Central Universities across the country. Vacant faculty positions must be filled up on a war footing and guest faculty or ad hoc professors should be engaged on short term basis.

Vacancies in the Indian Railways are to be filled on a priority basis. There are a total of 2,98,428 vacancies in the Indian Railways. Out of these, almost 25,000 posts are vacant in the East Coast Railway and South Central Railway where a large number of aspirants from Andhra Pradesh participate in the recruitment process.

The recruitment process of exams like RRB and NTPC should be streamlined by following an annual examination calendar to avoid delays and confusion. As a huge number of aspirants from Andhra Pradesh participate in the railway recruitment, I request that a Railway Recruitment Zone should be established in the State. Coming to operationalisation of the South Coast Railway Zone and expediting completion of pending railway projects in Andhra Pradesh, though eight years have passed since the bifurcation of Andhra Pradesh, the South Coast Railway Zone, promised in the AP Reorganisation Act, 2014 has still not been operationalised. I request the Minister to retain the Waltair Division as it would help in the growth of backward regions of North Coastal Andhra like Srikakulam and Vizianagaram. Economically important railway projects like Kadappa-Bangalore line should be completed at the earliest. I also request the Union Government to support Andhra Pradesh by financing the pending portion of the Bhadrachalam-Kovvur railway line which passes through a Left Eing Extremism affected area as the State is in revenue deficit. Central Universities and other prominent Institutes of the Union Government are functioning from temporary campuses in Andhra Pradesh. As a compensatory measure, after bifurcation of Andhra Pradesh, it was promised that many Central Government educational institutions would be established in Andhra Pradesh but the Central Universities in Anantapur and Vizianagaram, IIT and IISER in Tirupati are still functioning from temporary campuses even eight years after the bifurcation of the State. I request the Union Government to expedite the development of these institutions by providing adequate funds.

I urge the Central Government to provide sufficient funds, create facilities and appoint faculty without further delay in the Central

University of Anantapur in the State of Andhra Pradesh.

The transport and logistics sector is rapidly expanding due to the special focus being placed by the Government of India. … (*Interruptions*) In this regard, establishing the Gati Shakti Vishwavidyalaya is a welcome move. …(*Interruptions*) It would aid in reducing the skill gap in the transport sector, thereby kickstarting a virtuous cycle of economic growth and employment in the country. … (*Interruptions*) Thank you.

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।… (व्यवधान)

मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर, पिछले आठ वर्षों में क्रांतिकारी परिवर्तन तो हुए ही हैं, खासतौर पर उच्च शिक्षा में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने नयी शिक्षा नीति के तहत इस क्षेत्र में एक नया आयाम देने का काम किया है।… (व्यवधान)

महोदय, भारत सरकार को उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाए गए इस बिल का मैं हृदय से समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ।… (व्यवधान) इस बिल के माध्यम से सरकार गुजरात में बड़ौदा स्थित राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव लायी है।… (व्यवधान) मैं पुन: माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और इसका स्वागत करता हूँ।… (व्यवधान)

परिवहन क्षेत्र में तकनीकी के साथ बेहतर अनुसंधान के लिए एक नयी सोच के तहत शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।… (व्यवधान) दूरदर्शी सोच के अनुरूप और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार

नवाचार के लिए बधाई की पात्र है। राष्ट्रीय और सामरिक दृष्टिकोण से भारत में परिवहन को लेकर अपार संभावनाएं हैं।... (व्यवधान) चाहे वह भारत सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत निर्माण का प्रोजेक्ट हो, देश के किसी भी कोने में 24 घंटे के अन्दर सामान की डिलीवरी करने का सरकार का जो लक्ष्य है, ऐसे सभी क्षेत्रों में काफी तेजी से काम हो रहे हैं। आगामी कुछ वर्षों में हम अपने सपनों को सच करने ही वाले हैं।... (व्यवधान)

हमारे देश की जीडीपी का पहिया परिवहन है और इसे तेजी से नचाने के लिए अनेक पॉलिसीज लाई गई हैं, जिनमें इथेनॉल की पॉलिसी, ग्रीन फ्यूल की पॉलिसी, हाइड्रोजन फ्यूल की पॉलिसी है और अब गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना करके सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वह बहुत ही असाधारण है।... (व्यवधान) मैं समझता हूँ कि विश्वस्तर पर इस तरह की यूनिवर्सिटी पहले से चलाई जा रही है, उसको देश की धरती पर लाने का जो काम वर्तमान सरकान ने किया है, हम उसके लिए उसे कोटिश: धन्यवाद देते हैं।... (व्यवधान)

मेरा मानना है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय जैसी संस्थान से देश में न केवल तकनीकी और नवाचार आएगा, बल्कि दुनिया में यह भारत की कौशल क्षमता को एक अलग आयाम देने का काम करेगी।... (व्यवधान) मैं इस चर्चा के माध्यम से, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और उनका ध्यान पटना विश्वविद्यालय की तरफ भी ले जाना चाहूंगा।... (व्यवधान) वे बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं। पटना विश्वविद्यालय को सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग न जाने कितने समय से हो रही है।... (व्यवधान)

देश में जब यूनिवर्सिटीज खुली थीं, उन पांच विश्वविद्यालयों में से एक स्थान पटना विश्वविद्यालय का है। ... (व्यवधान) बिहार के लोग काफी दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। ... (व्यवधान) हाल में ही माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2017 में, जब पटना विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली समारोह मनाया जा रहा था, उसमें शिरकत करने का काम किया था। सरकार के पास देश भर में दस प्राइवेट और दस पब्लिक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज हैं। ...

(व्यवधान) पटना यूनिवर्सिटी भी इस योजना से जुड़े, इसके लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। ... (व्यवधान) वर्तमान में देश विश्वविद्यालयों की कमी से जूझ रहा है। ... (व्यवधान) देश के अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों की तुलना में यहां न तो छात्रों के लिए बेहतर रिसर्च लायक संस्थान हैं और न ही इन्हें सही माहौल मिल रहा है। ... (व्यवधान) मैं वर्तमान सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार में अन्य जगहों पर, जैसे मोतिहारी और गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं। ... (व्यवधान) बावजूद इसके मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पटना में भी इसकी आवश्यकता है। ... (व्यवधान) आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज न होने की वजह से बिहार के बहुत बच्चे देश के बाहर जाने का काम करते हैं। ... (व्यवधान) देश और दुनिया में आईटी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण शहर पटना आधुनिक शिक्षा के लिए अभी तक तरस रहा है। ... (व्यवधान) पटना यूनिवर्सिटी केवल पटना की ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। ... (व्यवधान) मैं समझता हूं कि यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होने की वजह से इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर में, गुणवत्ता में बहुत कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को दिल्ली और अन्य शहरों में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। ... (व्यवधान) यही नहीं, वहां बहुत गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके परिवारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ... (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार की राजधानी में पवित्र गंगा नदी के किनारे शानदार अतीत वाली पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर भारत सरकार देती है, माननीय मंत्री जी इस पर कृपा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि पाटलिपुत्र की इस भूमि पर, जो हमारी ऐतिहासिक भूमि रही है, उसमें से ज्ञान की गंगा देश भर में बहने लगेगी। ... (व्यवधान) दूसरों राज्यों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिन बच्चों को जाना पड़ता है, खास तौर पर वर्तमान में गरीब कल्याण के लिए जो हमारी समर्पित सरकार है, उसके द्वारा एक नया तरह का अवसर मिलेगा। ... (व्यवधान) मैं इसके लिए सरकार को आभार व्यक्त करूंगा। ... (व्यवधान)

इससे राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा, योग शिक्षकों के मार्गदर्शन से युवा शक्ति अर्थात बिहार के लोगों और बिहार के बच्चों को तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा। … (व्यवधान) इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से, केंद्र सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की कृपा प्रदान की जाए। … (व्यवधान) इससे बिहार की जनता और पाटलिपुत्र की जनता इस सरकार का आभार व्यक्त करेगी। … (व्यवधान) धन्यवाद।

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, I am thankful to you for allowing me to participate in this discussion … (*Interruptions*) Sir, I stand in support of the Central Universities (Amendment) Bill, 2022. The Bill proposes to provide for converting the National Rail and Transportation Institute (NRTI), a deemed to be university into a Central University. With the establishment of this university, the broad achievements will be that it will create a cadre of best in class transportation talent, facilitate industry career options, upskill and evolve the capability in transportation sector to cater to new industry demands, high quality education in research and skill development in various disciplines … (*Interruptions*) Sir, the establishment of this Vishwavidyalaya known as Gati Shakti Vishwavidyalaya, will also upskill and evolve capability in the transportation sector to cater to new industry demands through high quality teaching, research and skill development in various disciplines.

Sir, the establishment of the University shall foster collaboration between public sector, private industry and academia. … (*Interruptions*) It shall create a digitally-enabled environment that fosters and promotes the spirit of entrepreneurship among the students. With the establishment of the University, it will be possible to provide a base for in-depth research in transport sector which is needed in this current scenario. … (*Interruptions*) As a Central University, it will also be able

to attract the best of the academic industrial talent. Due to the stature of a Central University, innovative programme relevant to the current industries can be added. … (*Interruptions*) Sir, we must remember that because of the premier institutions like Indian Institute of Technology and Indian Institute of Management, we were able to give our youth the opportunity to excel and add them in our workforce. … (*Interruptions*) My only concern is that everything should not go to Gujarat. It should be equally distributed amongst all the regions. … (*Interruptions*) I would also request that a University of Tourism and Hospitality should be established in Anantnag. Sir, at the same time, I would also join the protest against the misuse of the agencies. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri K. Ram Mohan Naidu ji.

… (*Interruptions*)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you hon. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on this Bill. … (*Interruptions*)

At the outset, I welcome the upgradation of the National Rail and Transportation Institute (NRTI) in Gujarat to a Gati Shakti University with broader scope. Logistics is a key enabler of economic growth. … (*Interruptions*) If we focus on logistics development, we can reach the goal of a $ 5-trillion economy easily which we are trying to achieve. In fact, we can then create even higher goals for ourselves. To support this vision, there is a need to create more Transport and Logistics professionals. And to that extent, a University of Gati Shakti is a step in the right direction. … (*Interruptions*)

Sir, India has been at the heart of many crucial developments in science and technology. Be it the discovery of 'zero', the Raman Effect or the study of boson also known as God particle, our ancestors had achieved the zenith of human progress. Moreover, our country was the home to the finest ancient universities such as Nalanda, Taxila and Mithila. … (*Interruptions*)

However, sadly, somewhere down the line we have lost the edge globally. Considering this dire situation, I seek to highlight the issues and the possible solutions that the Government can take up. … (*Interruptions*)

Sir, as we all know, Indian Universities are still struggling on the global ranking charts. … (*Interruptions*) Though the number has been promising lately, which is 41, last year, however, we still have not been able to crack the global ranking. The reason for the underperformance of the Universities are largely attributed to following reasons – lack of global diversity in terms of foreign teachers and students; lack of global repute; inadequate student-faculty ratio; and obsolete research facilities. … (*Interruptions*)

Factoring this, I suggest that this newly upgraded university should have tie-ups with similar entities across the world while promoting indigenous knowledge and innovation. … (*Interruptions*)

As I understand, the Bill also provides for the establishment of additional University campuses and regional centres. … (*Interruptions*) Presently, such a campus is proposed to be set up in Kolkata and a regional centre in Kollam.

Considering the Indian peninsula to be the hub of maritime activity, I suggest that an additional campus could be set up in South India in the North Andhra Region, to be specific, Sir, where we already have a major port of Visakhapatnam. It will also bolster the Look-East Policy. … (*Interruptions*)

Sir, this is my last point and then I will finish.… (*Interruptions*) Before moving on to broader national issues, I would first like to address the problems within my own home-State. … (*Interruptions*) In 2014, the AP Reorganisation Act had promised a slew of universities and institutions which include IIIT, NIT, IIM, IISER, Central University, Petroleum University, etc. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (<u>व्यवधान</u>)

<u>14.59 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

-

<u>16.00 hrs</u>

The Lok Sabha reassembled at Sixteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : श्री के. राम मोहन नायडू जी, कृपया अपनी स्पीच कॉन्टीन्यू कीजिए।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Chairperson Sir. With your permission, I would like to continue my speech.

Hon. Chairperson Sir, according to data published by the Education Ministry in 2019, out of 6,043 faculty members at the 23 IITs, only 149 were SCs and 21 were STs, which account for less than three per cent of the total faculty members.

16.0½ hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Benny Behanan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

Similarly, out of the 642 faculty members across 13 IIMs, only four belong to SC category and one belongs to ST category. … (*Interruptions*) A similar pattern could also be seen in the University of Delhi where out of the total sanctioned posts of 264 professors, there are only three professors from SC category and none from the ST background. Furthermore, another set of recent data shows that there are glaring vacancies for teaching positions against the reserved category seats. … (*Interruptions*) As the data shows, the vacancy stood at 988 against the seats for SC category and 1761 against the seats for OBC category. So, I would like to request the hon. Minister concerned in the Central Government to take cognizance of this issue and take necessary steps to fill the vacant seats. … (*Interruptions*)

Sir, I would like to highlight a couple of more points, and after that I will finish. … (*Interruptions*) According to Global Innovation Index, India stands at 46th position which is highly under-rated for a country embarked on a path to become superpower.

Moreover, the budget that is allocated for the research-related departments is very small when compared with the total budget allocation. … (*Interruptions*) On top of this, the Government has slashed the funding for three major institutions up to Rs. 576 crore in the recent budget also. During the pandemic, the countries such as UK and USA had an edge over us in introducing vaccines on war footing. … (*Interruptions*) We are also trying for Atmanirbhar Bharat. So, my sincere request is to not cut the funding that is given to the R&D component. Even for setting up this Gati Shakti University, the most important thing that we should concentrate on is the R&D budget for this. … (*Interruptions*)

Other than that, I would like to highlight some points regarding the AP Reorganisation Act. There are a couple of universities. … (*Interruptions*) Sir, please give me one minute. This is my last point which is very important. … (*Interruptions*) I will just conclude. … (*Interruptions*)

Sir, the TDP Government ensured land allocation for these institutions according to the AP Reorganisation Act. … (*Interruptions*) In spite of eight years since the passing of the Act, the progress made on these universities is very slow. For example, the IIPE, NIDM, and IISER are still functioning in temporary campuses. … (*Interruptions*) So, I would request the hon. Minister to speed up the construction of these

campuses and also to hold the classes in their respective buildings. … (*Interruptions*)

Also, I would like to highlight a point regarding the construction of Tribal University. … (*Interruptions*) There is a very little budget for that. Our intent is to establish that in the tribal area for the welfare of tribal people. … (*Interruptions*) An amount of Rs. 56 crore against the required sum of Rs. 1500 crore is not doing justice for this. So, the Central Government should allocate more funds for this. With this, I conclude my speech. … (*Interruptions*)

Thank you. … (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, 21वीं सदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज सरकार की ओर से केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया है। … (व्यवधान) यूनिवर्सिटी एक्ट, 2009 में एक नयी धारा का संयोग करते हुए एक नया उपक्रम बनाया जा रहा है, उस पर लगभग 10 माननीय सदस्यों और रेल विभाग, आईटी एवं संचार विभाग के मंत्री श्री अश्विनी जी की इंटर्वेंशन के साथ एक सार्थक चर्चा समाप्त हुई है। … (व्यवधान)

महोदय, सभी ने इसका स्वागत किया है। इसकी आवश्यकता, समय एवं इसके अंदर पढ़ाए जाने वाले विषयों का उल्लेख किया गया है। … (व्यवधान) एक प्रकार से सभी ने, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इस नयी गति शक्ति यूनिवर्सिटी का समर्थन किया है। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। … (व्यवधान)

महोदय, हमारे दूरद्दष्टा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न केवल वर्तमान के बारे में योजना बनाते हैं, बल्कि भविष्य में जिस औद्योगिक क्रांति 4.0 की तरफ हम जा रहे हैं, आने वाली सदियों में क्या-क्या आवश्यकताएं होंगी, उनमें भारत कैसे स्थान लेगा, इन सभी संभावनाओं को नीति और कार्यक्रम में परिवर्तित करने का विजन रखने वाले भी हमारे प्रधान मंत्री जी हैं। … (व्यवधान)

गति शक्ति मिशन उनकी सोच का एक प्रतिफलन है।... (व्यवधान) उनकी सोच में एक बार यह आया कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अम्ब्रेला के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना है।... (व्यवधान) विभाग तो अलग-अलग होंगे।... (व्यवधान) रेल का अलग विभाग होगा।... (व्यवधान) रोड सेक्टर अलग विभाग से चलेगा।... (व्यवधान) राज्यों की भूमिका रहेगी।... (व्यवधान) कोर्ट्स की अपनी अलग पॉलिसी है।... (व्यवधान) इनलैंड वाटर इमर्ज कर रहा है।... (व्यवधान) एविएशन इंडस्ट्री की देश में काफी मात्रा में ग्रोथ हुई है।... (व्यवधान) इंटरनेट सर्विस, आज भारत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ 5जी का न केवल सपना देख रहा है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं इस पवित्र गृह में देश के सामने उल्लेख कराना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2022 के अंत तक यह देश टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होगा।... (व्यवधान) फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होगा।... (व्यवधान) 5जी की टेस्ट ड्राइव हमारे देश की आईआईटीज, दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, उनकी अगुवाई से आज हम उस सिद्धा तक पहुँच चुके हैं।... (व्यवधान)

महोदय, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े-बड़े कारखाने बड़े-बड़े उद्योग, बड़े-बड़े सामाजिक प्रकल्प आने वाले दिनों में खेती कहाँ होगी, सिंचाई कहाँ होगी, स्कूल कहाँ बनेगा, आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ होगा, उसके लिए एक मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है।... (व्यवधान)

महोदय, आज हमारी सरकार ने बाइसाग, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो इन्फार्मेटिक्स, जैसी संस्थाओं को इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की मान्यता भी दी है।... (व्यवधान)

यह सारी पृष्ठभूमि मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आज देश की आवश्यकता है कि इन सारे औद्योगिक इनिशिएटिव को ढांचागत परिवृद्धि को, इंफ्रास्ट्रक्चर विजन की अगर हम एक नॉलेज रिपॉजिटरी नहीं बनाएंगे, उसमें अनुसंधान नहीं होगा, उसमें विज्ञान का मिलाप नहीं होगा, वैश्विक टेक्नोलॉजी क्या-क्या चल रही हैं,

अगर हम उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेज भारत में नहीं लाएंगे तो हम देश की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे।... (व्यवधान)

16.07 hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Benny Behanan and some other hon. Members left the House.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: *इसी पृष्ठभूमि से गति शक्ति विश्वविद्यालय की कल्पना की गई है। वर्ष 2018 से रेल विभाग की अगुवाई से बड़ौदा में, उनका जो पुराना रेल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट था, उसको एक डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता देकर उसको एक विश्वविद्यालय बनाया गया था। बाद में जैसी समय की आवश्यकता हुई, मैंने बिल के इंट्रोडक्शन के समय उसकी पृष्ठभूमि को बताते हुए और सभी माननीय संसद सदस्यों ने उसका एक-एक फीचर कहा। किसी ने कहा कि इसका इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए। अगर ये वैश्विक स्तर के इंस्टिट्यूशन से टाईअप नहीं करेंगे, आज अगर मैं भारत के रेल विभाग का उदाहरण लूँ, भारत कम से कम, भारत की रेल कंपनियाँ, भारत सरकार की रेल संबंधी नीतियाँ, दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी में से कम से कम 20 देशों में भारत की रेल विभाग की फुटस्टेप है। हमारी कैपेसिटी केवल हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के गरीब देशों के लिए भी आवश्यक होती है। इसलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंस्टिट्यूशन बनाना हमारे मैन्डेट में है।*

महोदय, आज मैं एक आंकड़ा पार्लियामेंट के सामने रखता हूँ, भारत की नीति के हिसाब से 15 वर्ष की आयु से, जब किसी व्यक्ति की 15 वर्ष की आयु होती है, वह एक इकोनॉमिक यूनिट बन जाता है, वह रोजगार क्षम होता है। 15 से 25 वर्ष की आयु तक एक नौजवान, एक बालक विद्यार्थी की भूमिका में रहता है। ऐसी आज हमारे देश में 25.5 करोड़ की संख्या है। आज विभिन्न प्रकार के एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस में, शिक्षा अनुष्ठान में, वह स्कूल हो, 11 वीं-12 वीं की कक्षा हो या रिसर्च तक पढ़ाई हो, इसमें सिर्फ 11 करोड़ बच्चे आ पाते हैं।

चौदह करोड़ बच्चे काम पर बिना स्किल इको सिस्टम पर लग जाते हैं और वे पढ़ाई के लिए नहीं आ पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह मेनडेट है। आज उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27 परसेंट है। उसको वर्ष 2030 तक बढ़ा कर 50 प्रतिशत करना पड़ेगा। लेकिन भारत अभी नया सपना देख रहा है, अभी हमारे जो नौजवान आएंगे, उनके लिए रोजगार होना चाहिए, श्रम होना चाहिए। उनकी एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, न केवल एम्प्लॉयबिलिटी हो, न केवल वे जॉब सीकर बनें, बल्कि वे जॉब क्रिएटर भी बनें। ऐसी शिक्षा की कल्पना इस गति शक्ति के अंदर रखी गई है।

सभापति महोदय, न केवल टेक्नोलॉजी, न केवल साइंस, न केवल इंजीनियरिंग, न केवल मैथमेटिक्स, यह तो एक प्रकार से भारत की पहली स्टेम यूनिवर्सिटी बनेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह भी रिकमंड किया कि यह मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए।

सभापति महोदय, ये प्रकल्प लगते हैं, रेल, रोड होने के कारण विस्थापन भी होता है और विस्थापित लोगों की जिंदगी कैसे होती है, यह ह्यूमैनेटीज में पढ़ाया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में यह कल्पना की जा रही है कि ऐसी सारी विधाओं को भी पढ़ाया जाएगा, तब यह पूर्ण मात्रा में मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा। सभी ने इसका समर्थन किया है। यह एनईपी की आइलैंड है।

सभापति महोदय, आज मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि हम दुनिया के कई देशों में जाते हैं और भारत में भी पायलेट मोड में बुलेट ट्रेन वगैरह की बात आज घर-घर तक पहुंच गई है। वन्दे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगी है। उड़ान स्कीम आज सामान्य व्यक्ति की ऐस्पिरेशन की प्रतीक बन चुकी है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा, हमारे मित्र निशिकांत जी यहां पर बैठे हुए हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी जुलाई महीने में ही हमारे देश के पवित्रधाम देवघर जाकर नई हवाई पट्टी बनाकर आए हैं, एयरपोर्ट बना कर आए हैं। मैं खुद को संशोशित करता हूं कि हवाई पट्टी नहीं, बल्कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बना है। राजीव प्रताप रूडी जी विमान लेकर गए थे और कुछ मित्र भी साथ में गए थे तो सभी को

बधाई। आज देश के गरीबों की, दलितों की एवं पिछड़ों की आकांक्षाएं आकार ले रही हैं। देश के दूर-दराज इलाकों में एविएशन इंडस्ट्री मोदी सरकार में पहुंची है।

सभापति महोदय, यह बात केवल विमान उड़ान की नहीं है, इसमें विज्ञान भी जुड़ा है, इसमें अर्थशास्त्र भी जुड़ा है और इसमें अर्थ नीति का विकेंद्रीकरण भी जुड़ा है। यह सारा विषय गति शक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ाई की आवश्यकता का है। ड्राइवर लैस इंजन की बात कही जाती है। आखिर यह ड्राइवर लैस इंजन ऐसे तो नहीं चल जाएगा। उसके लिए रिसर्च, लोकलाइजेशन, लोक स्किल कैपेसिटी की आवश्यकता है। इसमें ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना की गई है कि इसमें न केवल उच्च शिक्षा की डिग्री दी जाएगी, बल्कि वर्तमान सारे सेक्टर्स में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने सभी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। वर्ष 2025 तक एक आकलन आ रहा है कि दुनिया में जितना काम लोग हाथ से करेंगे, उतना ही काम मशीन से होगा। आखिर मशीन के प्रशिक्षण की भी तो आवश्कयता होगी। भारत में कई काम बंद हो रहे हैं और कई नए काम सृजन हो रहे हैं। इन नये कामों के बारे में जानकारी और उनके प्रशिक्षण, उनके स्किल सर्टिफिकेशन इसी यूनिवर्सिटी में होंगे। ऐसे ही एक फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्सिटी है। जैसे मैंने उनको कहा कि यह एनईपी के उपरांत देश की पहली रिसर्च यूनिवर्सिटी, पहली आंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, पहली स्टेम यूनिवर्सिटी और पहली मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। इसमें स्टेम के साथ-साथ ह्यूमैनिटी और कॉमर्स भी है। आज रेलवे में एमबीए दो कोर्स में पढ़ाया जाता है। इसका व्यवसायीकरण कैसे होगा तो इसके बारे में भी चर्चा की जाती है और आने वाले दिनों में खर्चा कम हो, योजना सटीक तरीके से सही लाभार्थी तक पहुंचे, इसमें एक बड़े मास्टर प्लान की परिकल्पना की जा रही है। इसमें बायसैक को यह काम दिया गया है। मैं आज सदन में एक अच्छी सूचना देना चाहता हूं कि भारत के सभी राज्यों ने, अभी तो अच्छा हुआ कि शांति हो गई है। हमारे जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ सदस्य, राममोहन जैसे नौजवान साथी, चन्द्रशेखर बाबू जैसे साथियों ने इसका समर्थन किया है। इनको सच में इसमें रुचि थी और वे लोग बैठ कर इसको सुन रहे हैं।

उनकी उपस्थिति ही बड़ी अच्छी बात है। आज भले ही सदन में थोड़ी नोक-झोक हो, लेकिन बाइसा की गतिशक्ति मिशन में, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि भारत की सभी सरकारों ने आज सहयोग किया है, भारत के सभी विभाग अपना डाटा उसमें लेयरिंग करते जा रहे हैं। अब देखिए, आने वाले दो-चार साल के बाद, भारत में बीच-बीच में आती हैं, भारत में रेल पटरी कितनी जल्दी बन रही है। रोड कितनी जल्दी बन रही है। हमारे सामने इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का उदाहरण लें। सभापति महोदय, वर्ष 2020 में कोरोना के बीच में मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र का मातृस्थान भारत है, उसका नया मंदिर हम लोग बना रहे हैं और वर्ष 2023 तक यह बन कर रेडी हो जाएगा। यह है गतिशक्ति। इन सब की डॉक्युमेंटेशन, प्लानिंग, इम्पिलिमेंटेशन, इन सब में आधुनिक विधा की आवश्यकता होगी। ये सब एक, दो या पांच साल के लिए नहीं बन रहे हैं। ये आने वाली सदियां-सदियों तक के लिए बन रहे हैं, इसीलिए इसमें रिसर्च, विज्ञान, मानवता, व्यावसायिक पक्ष, इन सारे विषय की पढ़ाई और रिसर्च की आवश्यकता है। एक नयी कार्य संस्कृति भारत में विकसित हो रही है। जो कहा जाएगा, वह किया जाएगा। उसमें विश्वास बनता है। सभी के लिए किया जाएगा। सबको साथ ले कर किया जाएगा। इसी में सभी का विश्वास बढ़ रहा है। सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। गतिशक्ति उसका एक व्यावहारिक रूप है।

मैं इस बिल को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले एक शब्द में एक बात और कहना चाहूंगा। मैं संसद की इस गरिमामयी परिवेश का थोड़ा फायदा भी लेना चाहता हूँ। कई जगह पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्सपेंशन के बारे में कई सदस्यों ने उल्लेख किया है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनके सामने यह विषय कहना चाहता हूँ कि वह एक अलग विषय है। आज हम 21वीं सदी के नए विश्वविद्यालय की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें मैं आपका समर्थन मांग रहा हूँ। लेकिन एक संवैधानिक विषय को भी उठाया गया है। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विशेष कर समाज के वंचित वर्गों के पद खाली हैं। एससी, एसटी, ओबीसी तथा एक और वर्ग भी है, मोदी जी ने एक और समाज के तबके को आरक्षण देने की बात कही है, जिसे इकोनॉमिक वीकर सैक्शन कहा जाता है, जो दिया जाएगा, चारों वर्गों को दिया जाएगा। यह बात

सही है। जिन माननीय सदस्यों ने विषय को उठाया है, वह सही उठाया है कि कुछ-कुछ सैक्शन में दिया है। एससी, एसटी के पदों की भरपाई हो, यह वर्ष 2014 के उपरांत का विषय नहीं है न, यह तो पहले का विषय है। कारण खोजना पड़ेगा। संविधान सभा में, इस पवित्र गृह में चर्चा हुई थी कि आरक्षण हमारे समाज के कुछ भाई-बहनों को दिया जाएगा। संविधान सभा ने तय किया था। आखिर एक बार इस सदन को डिबेट करनी चाहिए कि किस सरकार के समय कितनी नियुक्तियां की गई हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मित्रों ने प्रश्न उठाया, मैं आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूँ। देश में पहली बार, वर्ष 2018 में देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक कानून लाया गया कि यह ऑप्शनल नहीं रहेगा। आपकी इच्छा पर नहीं रहेगा। समाज के वंचित वर्ग किसी के मोहताज के पात्र नहीं हैं। यह उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको देना ही पड़ेगा।

पहली बार पार्लियामेंट में, राज्य सभा में कानून लाया गया। वर्ष 2018 के बाद जो हायर एजुकेशन में पद रोस्टर के मुताबिक एससी, एसटी, ओबीसी और मैं फिर से जोड़ रहा हूँ कि इकोनॉमिक वीकर सैक्शन, इन चारों के लिए जो पद व्यवस्था के तहत हैं, उनको भरना पड़ेगा। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि आज मोदी जी की सरकार मिशन मोड पर, इन सारे पदों पर भर्ती करने का काम कर रही है। यह चूंकि एक ऐसा विषय है, मैं समाज की मानसिकता की बात को क्या कहूं, कुछ लोगों को लगता है कि बुद्धि एक विशेष वर्ग में ही अटक जाती है। मित्रों, ऐसा नहीं है।

बुद्धि समाज के सामान्य घरों में है, नहीं तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, देश के राष्ट्रपति नहीं होते, न नरेन्द्र मोदी, देश के प्रधान मंत्री होते और न द्रौपदी मुर्मू जी जैसी महिला आज देश की राष्ट्रपति होती। यह हमारी प्रतिबद्धता है। हमें उस पर विश्वास है, इसलिए तो मोदी जी वर्ष 2018-19 में नया कानून लाये। संसद की यह चिंता वाजिब है। उसको एक-डेढ़ साल के अन्दर, हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, विशेष ड्राइव करके भी भरा जाएगा। सदन आश्वस्त रहे, मोदी जी पर भरोसा करे। हम उसको करके रहेंगे।

सभापति जी, मैंने आपकी अनुमति से इस गति शक्ति विश्वविद्यालय की चर्चा के अवसर पर एक विषयांतर विषय पर कहा क्योंकि यह एक संवैधानिक विषय है।

सभापति जी, मैं ओडिशा से आता हूं। हमारे यहां एक कहावत है। हिन्दी में उसे ऐसे कहा जाता है - 'जो गलती किया, वही ज़ोर से चिल्ला देता है।' अगर मैं उसे ओड़िया में कहूं तो वह थोड़ा अन-पार्लियामेंट्री है।... (व्यवधान) अभी-अभी शायद सभापति जी ने किताब निकाली, मैं क्यों विवाद में जाऊँ? शायद वह अन-पार्लियामेंट्री हो जाएगा और फिर मेरे नाम पर कोई बड़े विद्वान लोग प्रिविलेज लगा देंगे, इसलिए मैं उसे नहीं कहता हूं। लेकिन, जो आज गलती करे, वही ज्यादा चिल्लाता है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी जिनके हाथ में शासन रहा, जिन्होंने 'गरीबी हटाओ' का नारा देकर दशकों तक इस सदन में राज किया, वे आज मोदी जी पर प्रश्न उठाते हैं। इसलिए, वे आज कहाँ हैं? यह अच्छा हुआ कि वे किसी का बहाना लेकर बॉयकॉट करके चले गए।... (व्यवधान) जनता उन्हें लम्बे समय तक बॉयकॉट करवाएगी। उन्हें प्रजातंत्र में विश्वास होना चाहिए।

सभापति जी, सदन के सहयोग की मैं कामना करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: महताब साहब, क्या आपके कुछ क्लैरिफिकेशन्स हैं?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मेरे तीन क्लैरिफिकेशन्स हैं।

After hearing such a spirited speech, I was so engrossed that practically most Members in this House might have lost track of the Bill itself. But let us come to the facts, the Bill, that is before us. I have referred to Section 3F, sub section (3), जो ऑरिजिनल बिल के साथ इन्सर्ट हुआ है - "Gati Shakti Vishwavidyalaya will be funded by the Central Government in the Ministry of Railways."

इस हाउस ने आज देखा कि एजुकेशन के माननीय मंत्री जी ने 1 अगस्त को यह बिल मूव किया और आज 3 अगस्त को यह चर्चा में है और थोड़ी देर में,

हाउस की सहमति से, संभवत: यह पारित भी हो जाएगा। इस बीच, चर्चा के भीतर, हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने भी इन्टरवीन किया।

जो डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटीज को हम सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, वह भी रेल मंत्रालय की ही है। अगर यह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, इसलिए एजुकेशन मंत्री और एजुकेशन मंत्रालय इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, तो मेरा प्रश्न सिम्पल है। रेल मंत्रालय की तरफ से इस यूनिवर्सिटी को चलाया जाएगा, खर्च किया जाएगा। मैं रेल मंत्री जी के वक्तव्य को सुन रहा था। क्या रेल बजट में इसके बारे में प्रोविजन है या आगे आपको सप्लीमेंटरी बजट में यह करना है, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। यह अब तक नहीं हुआ है।... (व्यवधान)

The proposals entail no financial implications - यही लिखा है। This also leads to a question. Whether the Centre plans to increase the budget allocated to the Ministry of Railways factoring into account the funding which has to be provided to Gati Shakti University. यह मेरा पहला प्रश्न है।

Proviso to Section 4, sub clause (1), जिसमें विश्वविद्यालय के टेन्योर के कर्मचारी, अधिकारी, प्रोफेसर, ये सारे रहेंगे, उनके बारे में है।

इसमें कहा गया है : "... same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions ...." यह तो ठीक है। It is a very welcome step. Normally, when the nomenclature of the University changes, most of the adopting agency or the संस्था, उसको एक्सेप्ट नहीं करती, परंतु आपने यहाँ विधेयक में इसको रखा है। But the question here is this. As I said, it is a very good provision, which keeps in mind the greater interest of employees. However, with regard to providing compensation to non-permanent employees, a consideration should be made for those non-permanent employees who have worked for a sustained time, and for such employees a compensation of three months should be provided. This is my suggestion.

The third point is that … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : मैं समझता हूँ कि इस पर डिबेट हो चुकी है।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि प्रश्न पूछ रहा हूँ। थर्ड रीडिंग में प्रश्न ही पूछा जाता है, यह आपको भी मालूम है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, हमारे कई सदस्य एक्स्प्लैन्टॉरी नोट पूछना चाहते हैं।

माननीय सभापति: ठीक है।

श्री भर्तृहरि महताब : यह प्रोविज़ो काफी लंबा है, पाँच लाइन का है। "Provided further that the Gati Shakti Vishwavidyalaya established as an University under section 3F shall take additional measures for providing high quality teaching, research and skill development in diverse disciplines related to transportation, technology and management including establishing centres in India and abroad, as may be required in the opinion of the said University." The question is this. There is no doubt that the activities to be undertaken by Gati Shakti are commendable, but there are no details with regard to the manner in which funds will be spent on each of these activities. Is there a mechanism to audit the expense of the University?

Initially, when the Central Universities Bill was passed in 2009, इसके बारे में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। उस समय प्रश्न यह था कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन होने की आवश्यकता है। 12-14 साल हो गए, कितने रिवर्स ब्रेन ड्रेन हुई हैं? यह एक प्रश्न है, जिसके ऊपर माननीय शिक्षा मंत्री विचार करें। क्योंकि, असली चीज वही थी कि हमारे यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेन्ट्स बनें और वहाँ से वापस आएं, इसके बारे में भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा एकमात्र सवाल है। यह जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनायी गई है, इसका सबने समर्थन किया है और हम लोग भी कर रहे हैं। माननीय मिनिस्टर साहब ने इस बात को बड़े ही विस्तार से बताया कि एससी, एसटी, वीकर सेक्शन और वंचित वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया गया है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे नहीं हैं। उसके साथ-साथ टीचर्स की बेहद कमी देखने को मिलती है। इस बिल के अंदर क्लॉज-5 में जो प्रोविजन दिया गया है, क्या उसमें एक और चीज ऐड करना उचित नहीं होगा, जिसमें 10 परसेंट से अधिक रिक्तियाँ कभी नहीं रहे? उसका प्रोविजन भी किया जाए। इसमें मैं माननीय मंत्री जी सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा किया जाएगा?

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद, सभापति महोदय। अभी माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, यह प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट दिखाता है कि वह किसी भी तरह से हमारे विद्यार्थियों को सारे स्किल्स और विद्याएं देना चाहते हैं तथा देश को आग बढ़ाना चाहते हैं।

सर, पुराने जमाने में तीन विश्वविद्यालय थे, जो बड़े विश्वविद्यालय थे- तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सौभाग्य से विक्रमशिला मेरा गाँव है। ... (व्यवधान) मैं अभी झारखंड से सांसद हूँ, लेकिन यह बिहार में है।

सभापति महोदय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को कंट्रोल करता था।

यह मैं नहीं कह रहा हूं, एएसआई ने जो बोर्ड मेरे गांव में लगाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय डूबने की कगार पर था, तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही उसका मास्टर विश्वविद्यालय था। वर्ष 2015 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने, जैसा मैंने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी पिछड़े क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो वर्ष 2015 में उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की घोषणा की और उसके लिए 400 करोड़ रुपये दे दिए। सात साल हो गए, माननीय प्रधान मंत्री जी की घोषणा हुई कि विक्रमशिला

विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन सात साल में वह विश्वविद्यालय नहीं बना है। क्या वह विश्वविद्यालय अपना चेहरा देख पाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन पाएगा और बनेगा तो कब तक बनेगा? मेरा आपसे यह प्रश्न है।

माननीय सभापति : विधेयक के बारे में पूछना उचित रहेगा। बाकी बातें आप बाद में पूछिए। कोई भी क्वैरी हो तो प्लीज, अपने को विधेयक तक ही सीमित रखिए।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): सर, मैं माफी चाहता हूं कि मेरा जो कहना है, उसका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि क्या एक सेंट्रल मिनिस्ट्री, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी को जम्मू-कश्मीर के अनन्तनाग में कंसीडर किया जाएगा?

माननीय सभापति : हसनैन साहब, वह अलग विषय है।

श्री हसनैन मसूदी : सर, मैंने पहले ही माफी चाही है। क्या आप इसे कंसीडर करेंगे?

माननीय सभापति : इस पर बाद में बात कर लीजिएगा। केवल बिल के बारे में बोलिए। अगर आपकी कोई क्वैरी हो तो उसे पूछिए।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): धन्यवाद सभापति महोदय। जब मेरा नंबर आया तो खाली बिल के बारे में, बाकी सब इतने लंबे-लंबे भाषण हो गए। मैं तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में ही बात कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और केन्द्रीय विश्वविद्यालय का यह अमेंडमेंट बिल है। पिछले दिनों मंत्री जी ने अवार्ड दिए, जिनकी रैंकिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई, उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री के माध्यम से अवार्ड दिए गए। उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया को भी अवार्ड दिया, जो कि तीसरे स्थान पर आई। माननीय मंत्री जी, क्या वजह है कि पिछले वर्ष 2020-21 में वहां का एलोकेशन ऑफ फंड 479 करोड़ रुपये था, जबकि इस बार 411 करोड़ रुपये है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका 1,520 करोड़ था, उसका 214 करोड़ रुपये हो गया। इसकी क्या वजह है? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दानिश जी, कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

… (व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति : आप सीधे सवाल पर आइए, जो आपकी क्वैरी है।

श्री रतन लाल कटारिया : गति शक्ति केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिल को लेकर जो आज प्रस्ताव पास होने जा रहा है, इससे देश के करोड़ों युवाओं की किस्मत बदलने वाली है। आज मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आदरणीय मंत्री जी ने इस महान सदन में उन लोगों के सभी भ्रम दूर कर दिए हैं।...(व्यवधान) मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं।... (व्यवधान) मैं बात कर रहा हूं।...(व्यवधान) मैं यह पूछना चाहता हूं ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको सब क्लियर है। आपको क्लेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है।

… (व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया : सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने आईआईएम को लेकर, आईआईटी को लेकर आरक्षण के मामले में प्रिअंबल ऑफ दी कांस्टीट्यूशन के बारे में मोदी जी के विजन को जिस तरह से यहां पर दोहराया है, क्या इसी प्रकार से गति शक्ति केन्द्रीय विश्वविद्यालय जो बनेगा, उसमें जो हमारे बच्चे हैं, उनको पूरा-पूरा लाभ मिलेगा? ... (व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): सभापति महोदय, 'गति शक्ति' द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाना अपने आप में फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ी शुरुआत है और सराहनीय है। यह हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाती है।

हम जिस ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, वह एयर पर है, सरफेस पर है, ट्रैक पर है, रिवर पर है और ओसिएन पर है। इसके लिए आज तक जिस दो फ्यूल का यूज होता था, एक स्टीम इंजन और दूसरा फ्यूल पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते थे। हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि हाइड्रो इंजन से चलने वाली गाड़ियां आएंगी। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के साथ-साथ सोलर एनर्जी के द्वारा चलने वाली गाड़ियां आएंगी। हम इनवायरमेंट को भी बचाएं और आने वाले भविष्य को भी बचाएं।

मेरा मंत्री जी से सिर्फ इतना ही प्रश्न है, क्या इस टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च और एजुकेशन और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हमारे छात्रों को दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो यह सराहनीय योगदान है। बड़ौदा के साथ-साथ इसकी फैकल्टी, इसके डिफरेंट डिविजन, डिफरेंट कैम्पस देश के विभिन्न जोनों में भी खोलने की जरूरत है।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, many hon. Members have spoken about vacancies in Central universities. More than 6000 vacancies are there. We have started a new Gati Shakti University which is a very specialised and a narrow field. Is there any study that is being done to find out where enough PhD scholars and enough faculty are available in this very specific field or are we going to start it like any other Central university and look for faculty or leave the faculty positions vacant in the coming years?

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि बिल रेलवे और परिवहन दोनों के संदर्भ में है और आज सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं एक्सिडेंट से होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि परिवहन के ऊपर खासतौर पर ड्राइविंग सिस्टम के ऊपर भी रिसर्च का कोई कार्य विश्वविद्यालय के अंदर होगा? मैं यही जानना चाहता हूं।

श्री अश्वनी वैष्णव: सभापति महोदय, जिस तरह से प्रश्न आए हैं, वह बहुत ही एनकरेजिंग है और सभी ने इस प्रस्ताव का बहुत ही खुले दिल से स्वागत किया

है। आज वाकई में देश में इसकी जरूरत है कि किस तरह से अति महत्पूर्ण लॉजिस्टिक ट्रांसपोटेशन सेक्टर के लिए एक यूनिवर्सिटी बनें। मैं दो प्रश्नों का जवाब दूंगा और शेष प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। फाइनेंस पर माननीय महताब साहब ने प्रश्न उठाया, इस बिल में अगर आप देखें तो बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है। "Any reference to the National Rail and Transportation Institute, Vadodara, in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to the Gati Shakti Vishwavidyala established under this Act. उसके आगे बहुत स्पष्ट रूप से सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक तरीके से पॉलिसी में कन्टीन्यूटी है। एनआरटीआई 2018 में बनाया गया था और उसको अपग्रेड किया जा रहा है। एनआरटीआई का जितना भी बजट है, उसके जितने भी काम हैं, वे सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होते हैं। इस वित्तीय वर्ष में एनआरटीआई का कितना बजट है? वर्ष 2022-23 में 166 करोड़ रुपये का बजट है। Mahtab sahab, I hope I have answered your question.

माननीय महताब साहब ने रिवर्स ब्रेन ड्रेन के बारे में कहा। यह मेरे सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज अगर हम टेलीकॉम सेक्टर देखें, स्टार्ट-अप सेक्टर देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स देखें और आईटी देखें। हर एक सेक्टर में दुनिया भर में भारत से निकल कर जो छात्र गए थे, उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया । उन्होंने हिन्दुस्तान में आकर अपने प्रतिभा और अपने अनुभव का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्टार्ट-अप इंडिया विजन के साथ जुड़ कर इतना बढ़िया इको-सिस्टम तैयार किया है कि आज भारत में 105 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, 74 हजार स्टार्ट अप हैं। दुनिया में भारत का नाम स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के हिसाब से जाना जाता है। धन्यवाद।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: माननीय सभापति जी, मेरे मित्र अश्विनी जी ने आदरणीय महताब जी द्वारा, फाइनेंशियल एलोकेशन रेलवे के बजट में है या नहीं, स्पेसिफिक प्रश्न के बारे में क्लेरिफिकेशन दी है। मैं इसे थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। यह बात सही है कि इसके एनविज़न के बारे में वर्ष 2016 में पहली बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था। वर्ष 2018 में उस समय के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने बहुत बारीकी से सब लोगों से चर्चा की थी, तब आपकी अध्यक्षता में रेलवे कमेटी

चलती थी, मुझे इतनी जानकारी है कि आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। यह रेलवे से शुरू हुआ। महोदय, मैं एक उदाहरण जोड़ना चाहता हूं, इन दिनों माननीय मोदी जी ने भारत की स्पेस पॉलिसी रिफार्म की है। स्पेस पहले एक सरकारी चीज थी, अब भारत के नौजवानों को, भारत के पढ़े-लिखे रिसचर्स को, नई पीढ़ी के लोगों को स्पेस सेंट्रिक एन्टरप्रिनयोर बनाने के लिए स्पेस पॉलिसी को अनबंडल किया है, व्यापक किया है। स्पेस रिलेटिड एडवांटेजेस क्या होंगी?

क्या नया एन्टरप्रिनयोरशिप आएगा? इन सबको ध्यान में रखते हुए इसके दायरे को बड़ा किया गया। अभी इसमें भी व्यवस्था की गई है। वर्तमान रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के दो हिस्से हैं। पॉलिसी का पार्ट भारत सरकार की सैंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत चलेगा। इसके वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स और एकेडेमिक करिकुलम यूनिवर्सिटी की तरह पॉलिसी के तहत होंगे। अगर हम सैक्टर स्पेसिफिक नहीं करेंगे, हम आवश्यकता के अनुसार विद्या को नहीं ढालेंगे।... (व्यवधान)

महोदय, अभी यह होता था कि आईआईटी हो, अन्य कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो या ग्रेजुएशन हो, पढ़ने के बाद एक या डेढ़ साल मैनेजमेंट ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। उसे दोबारा काम सीखना पड़ता था। डेढ़ या दो साल उसके लिए हुनर, इनोवेटिव और क्रिएटिव पीरियड होता है, उसमें विद्यार्थी रहते हुए वह कौन से काम में जाएगा, अगर उसकी पढ़ाई अभी से शुरू हो जाए और वह सीधा जाकर डिलीवरी कर सके, इसीलिए यह इंस्ट्रुमेंट बनाया गया है। इसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेन्ट्स कभी नहीं रहने वाले हैं।

महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न उठाया और बीच में एक अन्य क्वेरी थी कि कांट्रेक्चुअल टाइप के लोगों की सिक्योरिटी का क्या होगा? मैं आदरणीय महताब जी, बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पब्लिक पॉलिसी के एक्सपर्ट के सामने अपनी सरकार की एप्रोच के लिए निवेदन करना चाहता हूं, देखिए, in the world contractual model is no more a concern. यह एक अपॉरच्युनिटी है। एक व्यक्ति कहीं फैक्ट्री में काम करेगा, सीईओ के रूप में काम करेगा, इधर आकर दो क्लास लेकर पढ़ाएगा, उनके लिए मिनिमम रिम्युनरेशन व्यवस्था रहेगी।

हमारे देश में इस प्रकार के इनोवेटिव इंस्ट्रुमेंट धीरे-धीरे आईआईटीज़ में भी इमर्ज कर जाएंगे, आईआईएम में भी इमर्ज कर जाएंगे। हम इस प्रकार का एनविज़न करते हैं और इसलिए हमने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोविजन रखा है। हमें इसे बॉटम हेवी नहीं करना है। कभी-कभी लगता है कि यूनिवर्सिटी स्टुडेंट के लिए या यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोगों के लिए है। यह प्रश्न आ जाता है। इसी से बचने के लिए यह प्रोविजन रखा गया है।

अंत में एक बात है, इसके बारे में अश्विनी जी ने उत्तर दिया है। मैं इसका उत्तर दो उदाहरणों के साथ सदन में रखूंगा तो समझने के लिए अच्छा होगा। सैंट्रल यूनिवर्सिटी हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, केवल सरकारी फंडिंग से चले, हमें इस कल्पना को छोड़ना ही होगा। समाज समृद्ध होने लगा है। एनईपी ने कहा कि हमें पब्लिक डोनेशन से भी चलना पड़ेगा। महताब जी को उदाहरण अच्छा लगेगा, वह जिस प्रांत से आते हैं, संयोग से मैं भी वहीं से आता हूं। वहां के महानुभाव सुब्रतो बागची माइंडट्री के फाउंडर ने अपनी जिंदगी की अच्छी-खासी कमाई का लगभग 300 करोड़ रुपये से ज्यादा दान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलूरू को दिया है। अभी रितेश जी या अन्य मित्र राम मोहन जी कह रहे थे कि एडवांस रिसर्च क्यों नहीं हो रही है? भारत बायोटेक ने अकेले क्यों एक वैक्सीन निकाली, हम और वैक्सीन क्यों नहीं निकाल पाए? आईआईएससी में पहली बार 20 जून को माननीय प्रधान मंत्री जी के हाथ से पत्थर रखा गया, सुब्रतो बागची और उनके पार्टनर ने पैसा दिया।

300 करोड़ रुपये से ज्यादा पब्लिक फंडिंग हुई। उनके द्वारा पैसा देने से वहां यूनिवर्सिटी बनी। हमें कानपुर में भी एक सौभाग्य मिला। इंडिगो के प्रमुख स्टेक होल्डर राकेश गंगवाल और सिंघानिया जैसे चार-पांच आईआईटीयन कानपुर के पुराने प्रोडक्ट हैं। हमारे अश्विनी जी की वह पुरानी कैंपस है। मैं वहां गया था। वहां लगभग 300 करोड़ रुपये पब्लिक फंडिंग से आए। हमारे आईआईटीयन, आईआईएम और हमारे एलुमनी इसके लिए ताकत रखते हैं। वे समाज को लौटाना चाहते हैं। इसलिए, आप उसके लिए चिंतित न रहें। सरकार तो है ही। आज समाज भी संपन्न होने लगा है। उसकी फंडिंग से भी इंस्टिट्यूशन इमर्ज कर रहे हैं।

हमारे कई मित्रों ने कुछ अन्य विषय के बारे में कहा है। आपने उनको और हमें संरक्षण दिया है। लेकिन, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि रिजर्वेशन वगैरह की लिगेसी प्रॉब्लम हमारे कार्यकाल की देन नहीं है। पीएचडी करने में पांच साल लगते हैं। कुल मिलाकर 75 साल की जर्नी में माननीय मोदी जी की 8 साल की जिम्मेवारी है। कुछ लिगेसी इश्यु के लिए हमारी नैतिकता है। सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए हमारे पास मोरल पावर है। बाकी विषयों, जिसको दानिश जी और अन्य लोगों ने उठाया है, हम उनसे मिलकर सभी विषयों के बारे में बता देंगे। मेरे पास बकायदा तथ्य आधारित रिपोर्ट है। यह इस विषय से संबंधित नहीं है। इसलिए, उसका उत्तर मैं नहीं देता हूं।

आपने मुझे पुन: एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन दिए हैं, परन्तु वे उपस्थित नहीं हैं। इसीलिए, मैं सारे खंडों को एक साथ सभा के निर्णय के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये ।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

-

-